अब लय पकड़ने लगा मानसून

152 .5 मिमी बारिश हो गई 21 जुलाई तक जिले में

नागपुर, निज संवाददाता. जून महीने में कमजोर प्रदर्शन के बाद अब जिले में मानसून ने लय पकड़ना शुरू किया है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 1 से 21 जुलाई की सुबह 8.30 बजे तक कुल 152.5 मिमी बारिश हो चुकी है. बादलों के बरसने का सिलसिला अभी जारी है. विभाग के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके चलते जिले में 27 जुलाई तक कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

बताते चलें कि नागपुर जिले में जुलाई महीने की औसत वर्ष 347.7 मिमी है. बीते 10 वर्षों में केवल वर्ष 2017 को छोड़ दें तो पिछले वर्ष 2025 तक जुलाई के महीने में औसत के कही अधिक बारिश हुई है. जून महीने का बैकलाग बारिश ने हर वर्ष जुलाई में पूर्ण किया है. इस वर्ष जून के महीने में जिले में कुल 102.3

मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि सामान्य बारिश 166.3 मिमी रही है. जून के महीने में 61.5 प्रतिशत बारिश हुई. वहीं जुलाई महीने में अब तक 152.5 मिमी बारिश हुई मतलब 1 जून से 21 जुलाई की सुबह 8.30 बजे तक कुल 254.8 मिमी बारिश हो चुकी है.

यह बीते वर्ष 2025 से काफी कम है. पिछले वर्ष इस तारीख तक कुल 429.6 मिमी वर्षा हो चुकी थी.

एक ही दिन में 27.3 मिमी बारिश: संपूर्ण जिले में 20 जुलाई की सुबह 8.30 बजे से 21 जुलाई की सुबह 8.30 बजे तक औसत 27.5 मिमी बारिश होने की जानकारी विभाग ने दी है. इन 24 घंटों में नागपुर सिटी में 28.9 मिमी, कामठी तहसील में 19.7 मिमी, हिंगणा में 28.7 मिमी, रामटेक में 30.7 मिमी, पारशिवनी में 22.1 मिमी, मौदा में सर्वाधिक 60.5 मिमी, काटोल 20.9 मिमी, नरखेड़ 19.9 मिमी, सावनेर 28.0 मिमी, कलमेश्वर 21.2 मिमी, उमरेड 27.2 मिमी, भिवापुर 23.6 मिमी और कुही में 17.7 मिमी बारिश एक ही दिन में दर्ज की गई.

महीने के अंत तक औसत पूरा होने की संभावना: जुलाई महीने की औसत बारिश 347.7 मिमी है. जिस तरह से बादल मेहरबान होते दिख रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक बादल यह टारगेट पूरा कर लेंगे. वर्ष 2016 से 2025 तक का रिकार्ड देखें तो जुलाई 2017 और 2020 को छोड़ कर शेष सभी वर्ष इस माह 400 मिमी से अधिक बारिश दर्ज हुई है. उक्त दो वर्ष क्रमशः 324.7 और 378.6 मिमी बारिश हुई थी. वर्ष 2022 में तो रिकार्डतोड़ 628.7 मिमी बारिश हुई थी.

किसानों को मिली राहत

खरीफ बुआई के लिए अनुकूल वातावरण बनने से अब किसानों को राहत मिली है. जून के महीने में पहले तीन सप्ताह तक तो बुआई के लायक बारिश ही नहीं हुई थी. कृषि विभाग व सरकार द्वारा अपील की गई थी कि जब तक 100 मिमी से अधिक बारिश नहीं होती, बुआई न करें. हालांकि जिले के कुछ भागों में जून के अंतिम सप्ताह तक 15 से 20 फीसदी बुआई हो चुकी थी. जून के अंत व जुलाई के पहले सप्ताह तक जब बारिश 100 मिमी के ऊपर पहुंच गई तब किसानों ने बुआई का काम शुरू किया. कपास, सोयाबीन, तुअर आदि के अंकुर भी निकल गए. लेकिन बीच में फिर बादलों की दगाबाजी के चलते किसानों के माथों पर चिंता की लकीर नजर आने लगी थी. अब जब मानसून लय में नजर आ रहा है और जिले भर में बादल बरस रहे हैं तो किसानों के चेहरों पर राहत नजर आ रही है.

जुआ खेलते धरे गए 15 जुआरी, 90,400 रुपये का माल जब्त

नागपुर. वाठोड़ा पुलिस ने खबर के आधार पर छापेमारी की. 15 जुआरियों को ताश के पत्तों पर बाजी लगाते रंगेहाथ पकड़ा. उनसे 90,400 रुपये का माल जब्त किया गया. पकड़े गए आरोपियों में रमना मारोती निवासी कार्तिक सुनील सपाटे (26), चैतन्येश्वरनगर निवासी मंगेश विट्ठल खंडारे (25), गरीब नवाज चौक, वाठोड़ा निवासी शहबाज कलाम शेख (28), श्रीरामनगर निवासी अजिंक्य देवलाल लोंढे (32), राहुल अनिल जाधव (32), प्रतीक प्रमोद तल्हार (25), भरतवाड़ा निवासी आशीष कृष्णराव काले (40), सूरजनगर निवासी राजेंद्र सेवकराम जांगले (25), हनुमाननगर, उमरेड रोड निवासी अर्षद शेख नदीम शेख (25), खुंडेनगर निवासी अमोल प्रमोद सौंदरकर (28), पार्वतीनगर, वाठोड़ा निवासी मंगेश चंद्रशेखर मेहर (22), छत्रपतिनगर, खरबी निवासी अनुराग राजू हिरणखेड़े (19), खरबी टी प्वाइंट निवासी ओंकार प्रकाश पराते (24), ओमसाईनगर, दिघोरी निवासी अंशुल उरकुड़ा चिंचुलीकर (28) और खरबी निवासी पारस सुरेश चौधरी (22) का समावेश है.

ठग प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ एफआईआर

नागपुर. फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठग प्रापर्टी डीलरों ने एक व्यक्ति को 45 लाख रुपये का चूना लगा दिया. यशोधरानगर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोपियों में लघुवेतन कालोनी निवासी नित्यानंद प्रेमानंद रामटेके, चेतानंद प्रेमानंद रामटेके, दीनदयालनगर निवासी अंशु पुरुषोत्तम बजाज, कल्पनानगर निवासी राजेश हंसराज पंजवानी, अंसारनगर, मोमिनपुरा निवासी शब्बीर अहमद नूर अहमद और हैदरी रोड निवासी मोहम्मद युनुस मोहम्मद इद्रीस अंसारी का समावेश का समावेश है.

पुलिस ने अंसारनगर, मोमिनपुरा निवासी निजामुद्दिन महमूद अहमद (52) की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. निजामुद्दिन को प्लाट खरीदना था. नवंबर 2020 में उन्होंने आरोपियों से संपर्क किया. आरोपियों ने मौजा वांजरा में एक खेज जमीन पर अपना लेआउट बताया, जिसमें निजामुद्दिन ने 5000 वर्ग फुट का प्लाट पसंद किया. फर्जी दस्तावेजों के जरिए आरोपियों ने उनके साथ सौदा तय किया. दिसंबर 2023 तक आरोपियों ने समय-समय पर उनसे कुल 45 लाख रुपये लिए. लंबा समय बीत जाने के बावजूद न तो प्लाट की रजिस्ट्री करवाई और न उन्हें दस्तावेज दिए गए. जांच पड़ताल करने पर निजामुद्दिन को पता चला कि जिस प्लाट का सौदा उनके साथ किया गया है, वह जमीन आरोपियों की नहीं है. फर्जी सेल डीड और सातबारा के जरिए उन्हें फंसाया गया. उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करते रहे. आखिर परेशान होकर निजामुद्दिन ने पुलिस से शिकायत की.

चाकू के साथ धराया अपराधी

नागपुर. क्राइम ब्रांच की टीम ने लकड़गंज परिसर में गश्त के दौरान एक अपराधी को चाकू के साथ गिरफ्तार किया. पकड़ा गया आरोपी गंगा-जमुना बस्ती निवासी देवेश चमन कर्मावत (24) बताया गया. पुलिस दस्ता सोमवार की रात 10 बजे के दौरान गंगा-जमुना परिसर में गश्त कर रहा था. इसी दौरान देवेश संदेहास्पद स्थिति में घूमता दिखाई दिया. उसे पकड़कर तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ा चाकू बरामद हुआ. आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को संदेह है कि वह किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से हथियार लेकर घूम रहा था.

एक नजर में

पिछले 24 घंटे में औसतन 3.1 मिमी वर्षा दर्ज

बैतूल। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान औसतन 3.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक, भू-अभिलेख ने बताया कि 20 जुलाई प्रात: 8 बजे से 21 जुलाई प्रात: 8 बजे तक जिले के विभिन्न वर्षामापी केंद्रों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। उन्होंने बताया कि बैतूल में 2.0 मिमी, घोड़ाडोंगरी में 0.0 मिमी, चिचोली में 0.0 मिमी, शाहपुर में 3.0 मिमी, मुलताई में 13.4 मिमी, प्रभात पट्टन में 9.0 मिमी, आमला में 3.0 मिमी, भैंसदेही में 0.0 मिमी, आठनेर में 0.0 मिमी तथा भीमपुर में 0.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले में वर्षा ऋतु 2026-27 में अब तक औसतन 310.7 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। वहीं गत वर्ष 2025-26 में अब तक 367.1 मिमी वर्षा दर्ज हुई थी। उल्लेखनीय है कि जिले की सामान्य औसत वर्षा 1083.9 मिमी है तथा गत वर्ष की सामान्य औसत वर्षा 1097.4 मिमी रही थी।

एकादशी व्रत पूजन अनुष्ठान समारोह 25 को

बैतूल। युवा साहू समाज सेवा संगठन जिला बैतूल के तत्वाधान में देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर व्रत पूजन अनुष्ठान समारोह का आयोजन 25 जुलाई, शनिवार को शाम 6 बजे तुलसी भवन, विनोबा वार्ड, बैतूल में किया जाएगा। पंडित पुष्पेंद्र तिवारी ने बताया कि देवशयनी एकादशी का मुख्य महत्व भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और चातुर्मास की शुरुआत से जुड़ा है। इसी दिन से भगवान विष्णु चार महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार निष्काम भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करने से साधक को सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। चातुर्मास के इन चार महीनों में अच्छे कर्म, सात्विक भोजन और संयमित जीवन जीने का संकल्प लिया जाता है। शास्त्रों में इसका फल कई गुना अधिक माना गया है। पं. तिवारी ने बताया कि देवशयनी के दिन से ही चातुर्मास का पवित्र काल शुरू होता है। इसलिए शाम को भगवान को शयन के लिए आमंत्रित करते हुए सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम मंत्र का उच्चारण किया जाएगा।इस प्रकार शास्त्रांगत विधि से श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाएगी।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बैतूल लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम

बैतूल। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जून-2026 माह की प्रदेश स्तरीय नगरीय निकायों की ग्रेडिंग में बैतूल जिले ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया है। जिले ने 98.27 अंक प्राप्त करते हुए पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह उपलब्धि नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण के प्रति जिला प्रशासन की प्रभावी कार्यप्रणाली, जवाबदेही और सुशासन का प्रमाण मानी जा रही है। जून-2026 की ग्रेडिंग में बैतूल जिले के सभी नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन

किया। नगर परिषद चिचोली, नगर पालिका परिषद बैतूल और नगर परिषद भैंसदेही ने 100 प्रतिशत स्कोर हासिल किया। नगर पालिका परिषद आमला ने 99.52 प्रतिशत, नगर पालिका परिषद सारनी ने 96.92 प्रतिशत, नगर पालिका परिषद मुलताई ने 95.38 प्रतिशत, नगर परिषद बैतूल बाजार ने 95.00 प्रतिशत, नगर परिषद आठनेर ने 94.55 प्रतिशत, नगर परिषद घोड़ाडोंगरी ने 90.00 प्रतिशत तथा नगर परिषद शाहपुर ने 87.14 प्रतिशत स्कोर प्राप्त किया। जिले में सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन नगर पालिका परिषद बैतूल का रहा, जहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की सर्वाधिक 230 शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करते हुए 100 प्रतिशत स्कोर प्राप्त किया गया। इसे प्रभावी शिकायत प्रबंधन और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का उदाहरण माना जा रहा है। जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), बैतूल के परियोजना अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी नगरीय निकायों और संबंधित अधिकारियों ने टीम भावना के साथ कार्य किया।

निर्माण की जांच कर दोषियों पर हो कार्रवाई

मुलताई। नगर में निर्माणाधीन सीएम राईस स्कूल के निर्माण में तकनीकी रूप से हो रही खामियों की जांच कराकर दोषी अधिकारियो एवं निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जनआंदोलन मंच के अनिल सोनी ने मुख्य सचिव अनुराग जैन एवं कलेक्टर को सम्बोधित शिकायत मंगलवार की जनसुनवाई में सौपी है।अनिल सोनी द्वारा की गई शिकायत में बताया करोडो रूपये की लागत से मुलताई में सीएम राइज स्कूल का निर्माण जारी है,इस भवन का ड्राइंग एवं डिजाईनिंग कार्य इप्को विभाग द्वारा नियुक्त आर्किटेक्ट द्वारा किया गया है,ब्राईको स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आफिस में बैठे बैठे गुड फार कंस्ट्रक्शन के रूप में अनुमोदित किया गया है जो कि बडा ही फर्जी किया गया है। निर्माण कार्य का क्रियान्वयन विभाग व संविदाकार द्वारा किया जा रहा है जिस में इन्होने इसमें कोई जवाबदारी नही निभाई गई। निरीक्षण के दौरान सड़क पर ढलान का गलत बनाया गया है जिसके कारण वर्षा जल का निकास बाधित होकर जल भराव हो रहा है। भवन में कारीडोर के कुछ स्थानो पर प्रकाश व्यवस्था अप्राप्त होने से दिन में भी अंधकार जैसी स्थिति हो रही है। जल भराव के कारण सड़क की गुणवत्ता उपयोगिता प्रभावित हो रही है जिससे करोड़ो रूपयो का भ्रष्टाचार हो रहा है।उक्त बिन्दूओ में ड्राइंग एवं डिजाईनिंग की जिम्मेदारी इपको विभाग एवं नियुक्त आरके ट्रेक,ड्राइंग अनुमोदन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग निर्माण कार्य की जिम्मेदारी क्रियान्वयन विभाग पी आईयू एवं सविंदाकार गुणवता नियत्रण एवं निगरानी पीआईयू एवं सभी निरिक्षण दल के अधिकारी शामिल है। शिकायत में घटिया निर्माण के जिम्मेदार विभाग प्रमुख, पर कार्रवाई करने की मांग की है।

50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर खत्म, विक्रेता परेशान

बैतूल। जिला कोषालय बैतूल में पिछले करीब डेढ़ महीने से 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर उपलब्ध नहीं होने से आम लोगों के साथ स्टाम्प विक्रेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में समस्त स्टाम्प विक्रेताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द व्यवस्था कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि बैतूल कोषालय ने 1 जून 2026 को स्टाम्प पेपर समाप्त होने की सूचना भोपाल कोषालय को भेज दी थी। वहीं जिला पंजीयक बैतूल ने भी 4 जून 2026 को पंजीयन महानिरीक्षक भोपाल को पत्र भेजा, लेकिन अब तक स्टाम्प पेपर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके कारण स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प नहीं मिल रहे हैं और आम लोगों के जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्टांप विक्रेता श्री अवस्थी ने बताया कि कंप्यूटराइज्ड स्टाम्प बनाने वाले सर्विस प्रोवाइडर भी सर्वर डाउन होने का हवाला देकर स्टाम्प जारी नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टाम्प तैयार करने में 30 से 40 मिनट लगते हैं, जबकि सर्वर की समस्या होने पर एक से दो घंटे तक का समय लग जाता है। ऐसे में एक सर्विस प्रोवाइडर पूरे दिन में मुश्किल से 10 स्टाम्प ही बना पाता है। स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि स्टाम्प पेपर नहीं मिलने के कारण उनका रोजगार प्रभावित हो गया है।

भौंरा बस स्टैंड पर गूंजा नशामुक्ति का संदेश

भौंरा। समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के तहत मंगलवार को भौंरा पुलिस ने बस स्टैंड परिसर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, वाहन चालकों एवं आम नागरिकों से संवाद कर उन्हें नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। पुलिस हेड कांस्टेबल केएल नागले ने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि परिवार और सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। लोगों से अपील की गई कि वे स्वयं नशे से

दूर रहें और अपने परिवार, विशेषकर युवाओं को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। अभियान के दौरान नागरिकों को यह भी समझाया गया कि यदि क्षेत्र में कहीं अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी या सेवन की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भौंरा पुलिस के अनुसार नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के तहत क्षेत्र में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन शिविर 10 अगस्त को लगेंगे

बैतूल। युवा साहू समाज सेवा संगठन जिला बैतूल एवं चिरायु मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बैरागढ़ भोपाल के तत्वाधान में 10 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आठनेर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदही एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमपुर में विशाल मोतियाबिंद जांच परामर्श एवं ऑपरेशन शिविर के आयोजन किए जाएंगे। आयोजन समिति के प्रहलाद साहू एवं गोपाल साहू ने बताया शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन एवं कृत्रिम लैंस प्रत्यारोपण टांका रहित एवं फेको पद्धति द्वारा किए जाएंगे। सभी मरीजों को शिविर स्थल से उसी दिन बस के माध्यम से चिरायु मेडिकल कॉलेज बैरागढ़ भोपाल ले जाया जाएगा एवं वहां पर सभी मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को आवास, जांच, ऑपरेशन, दवाइयां की व्यवस्था एवं आत्मीयता पूर्वक सेवा की जाएगी। ऑपरेशन के बाद मरीज को पुन: शिविर स्थल पर लाया जाएगा जहां से सभी मरीज अपने घर को जा सकेंगे। श्री साहू ने आठनेर , भैंसदेही एवं भीमपुर के 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धि जनों से इस शिविर का लाभ लेने का आग्रह किया है।

निजी विद्यालयों की मनमानी से पालकों में आक्रोश

पाथाखेड़ा। सारनी से लेकर घोड़ाडोंगरी मार्ग के आसपास संचालित कुछ निजी विद्यालयों पर मनमाने ढंग से शुल्क वसूलने, बार-बार पाठ्यपुस्तकें एवं स्कूल ड्रेस बदलने तथा शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने के आरोपों ने अभिभावकों में नाराजगी बढ़ा दी है।

आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों का कहना है कि बढ़ती फीस और अतिरिक्त खर्चों ने बच्चों की शिक्षा का बोझ काफी बढ़ा दिया है। अभिभावकों का आरोप है कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क संबंधी नियमों के बावजूद कई विद्यालय निर्धारित सीमा से अधिक फीस जमा कराने का दबाव बना कर ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में नई पुस्तकें, अलग प्रकाशकों की सामग्री तथा नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे हजारों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार परिवारों पर पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि निजी विद्यालयों की नियमित एवं प्रभावी जांच नहीं होने के कारण कुछ विद्यालय मनमाने तरीके से संचालन कर रहे हैं। कई अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों (बी.एड., डी.एड.) की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है तथा शिक्षकों को नियमानुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई एक्ट) तथा मध्यप्रदेश में निजी विद्यालयों से संबंधित प्रचलित नियमों के तहत विद्यालयों को निर्धारित मानकों और शुल्क संबंधी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। यदि किसी संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर सकता है।

सकारात्मक बदलाव के लिए अर्जित ज्ञान का करें उपयोग

बैतूल। आठनेर में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत समाज कार्य के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का सम्मानपूर्वक विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों से अर्जित ज्ञान को समाज सेवा से जोड़ते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में सभी फायनल ईयर के विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गईं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड आठनेर की विकासखंड समन्वयक मधु चौहान

ने जन अभियान परिषद द्वारा पाठ्यक्रम को चलाने के उद्देश्य एवं पूरे सत्र की गतिविधियों का प्रतिवेदन उपस्थित लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए परिषद के नर्मदापुरम संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी ने कहा कि सीएमसीएलडीपी पाठ्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा,संवेदना और विकास की रोशनी पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने अध्ययन से अर्जित ज्ञान एवं कौशल का उपयोग समाज के वंचित,जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के उत्थान,जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक जागरूकता के लिए करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आठनेर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि एक सच्चे समाजसेवी की पहचान उसके समर्पण, नैतिकता, जनसेवा और सकारात्मक नेतृत्व से होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नैतिक मूल्यों, एवं जनहित की भावना के साथ कार्य करें, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

चलो मोबिलिटी की मनमानी, प्रशासन और पदाधिकारी भी मौन

बस चेकर्स के परिवारों पर भुखमरी का संकट

नागपुर. परिवहन विभाग में ड्राइवर और कंडक्टर का मसला भले ही हल हुआ हो, लेकिन अब बस चेकर्स को न्याय नहीं मिल पाने के कारण परिवारों पर भुखमरी का संकट है. जानकारों की मानें तो चलो मोबिलिटी एप कंपनी की मनमानी के कारण आपली बस सेवा के 42 बस चेकर्स और उनके परिवार वर्तमान में भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं. महीना बीत जाने के बावजूद इन कर्मचारियों के हाथ में वेतन का एक रुपया भी नहीं आया. हालत यह है कि घरों में राशन की कमी है, बच्चों के स्कूल की फीस बकाया है और मकान मालिक घरों में ताला लगाने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका का परिवहन विभाग प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है.

प्रशासन और पदाधिकारियों का खुला भेदभाव

सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में प्रशासन और राजनीतिक दलों का दोहरा रवैया सामने आया है. यदि आपली बस के चालकों और कंडक्टरों का वेतन 2 दिन भी रुक जाता है, तो तुरंत आंदोलन, मोर्चे और हड़ताल शुरू हो जाते हैं. ऐसे समय में बीएमएस, उबाठा और राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसे कई राजनीतिक दल तुरंत उनके समर्थन में दौड़ पड़ते हैं. यहां तक कि महापौर नीता ठाकरे खुद बस डिपो पहुंच जाती हैं और परिवहन सभापति मंगला खेकरे आपात बैठक बुलाकर तुरंत फंड जारी करवा देती हैं लेकिन जब बात इन 42 चेकर्स की आती है, तो कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है. वर्तमान में पूरा महीना बिना वेतन के बीत गया, लेकिन कोई नेता या अधिकारी इनका हाल पूछने नहीं आया. इसका मुख्य कारण यह है कि इन चेकर्स का कोई अपना संगठन नहीं है. इन्हें कोई राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं है और न ही इनमें वोटों की कोई बड़ी ताकत है।

क्या हम इंसान नहीं हैं : संतप्त चेकर्स का दर्द

अपना दर्द बयां करते हुए एक चेकर ने रोते हुए सवाल किया, हम बस में चढ़ते हैं, लोगों की गालियां सुनते हैं, मारपीट का सामना करते हैं, टिकट चेक करते हैं और जुर्माना वसूलते हैं. मनपा की आय में वृद्धि करते हैं. अपनी जान जोखिम में डालकर हम 14-14 घंटे तक खड़े रहते हैं. फिर हमारा वेतन कम क्यों है? और हमें समय पर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा?

श्रम कानूनों की उड़ रहीं सरेआम धज्जियां

काम में जोखिम और जिम्मेदारी अधिक होने के कारण चेकर्स का वेतन चालकों और वाहकों से अधिक होना चाहिए लेकिन वास्तविकता यह है कि इनका वेतन उनसे कम है और वह भी समय पर नहीं मिलता. श्रम कानून के अनुसार हर कर्मचारी को समय पर वेतन, न्यूनतम मजदूरी, 8 घंटे की शिफ्ट और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए. इसके ठीक विपरीत, चलो मोबिलिटी कंपनी अपने चेकर्स से 12 से 14 घंटे तक काम ले रही है. इन कर्मचारियों को न तो कोई साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, न ओवरटाइम का पैसा, न मेडिकल सुविधा और न ही त्योहारों पर कोई अवकाश दिया जाता है.

करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट, चेकर्स को देने के लिए निधि नहीं

एक तरफ चलो मोबिलिटी को करोड़ों रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और कंपनी भारी मुनाफा कमा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों को पगार देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं. यह श्रम कानूनों का सीधा और सरेआम उल्लंघन है.

पीएम श्री स्कूलों को पूरा, बाकी छात्रों को कम निधि

32 स्कूल पीएम श्री योजना के

1,512 स्कूल समग्र शिक्षा अभियान के

240 रुपये प्रति यूनिफॉर्म की दर से निधि

मुफ्त यूनिफॉर्म योजना में भेदभाव

नागपुर, महानगर संवाददाता. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की योजना के क्रियान्वयन को लेकर भेदभाव की स्थिति सामने आई है. पीएम श्री योजना के तहत आने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को दो यूनिफॉर्म का पूरा अनुदान एक साथ दिया गया, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत आने वाले विद्यार्थियों को केवल एक यूनिफॉर्म का ही पैसा मिला और वह भी निर्धारित राशि से कम.सरकारी योजना के अनुसार प्रत्येक छात्र को दो यूनिफॉर्म के लिए अनुदान दिया जाता है. प्रत्येक यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपये निर्धारित हैं लेकिन समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यार्थियों को केवल 240 रुपये ही दिए गए. यानी प्रति यूनिफॉर्म 60 रुपये कम मिले हैं. वहीं दूसरी यूनिफॉर्म की राशि कब मिलेगी, इस बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. इसके कारण अधिकांश विद्यार्थियों को पूरे सत्र में एक ही यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना पड़ रहा है. दूसरी ओर पीएम श्री योजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को दोनों यूनिफॉर्म का पूरा अनुदान एकमुश्त उपलब्ध करा दिया गया है. इसे लेकर शिक्षा क्षेत्र में दोहरी नीति अपनाने और विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किए जाने की आलोचना हो रही है.

आईडी कार्ड के लिए भी अनुदान

पीएम श्री योजना के तहत विद्यार्थियों को डिजिटल पहचान पत्र (आईडी कार्ड) के लिए भी अलग से अनुदान दिया गया है. इन आईडी कार्डों पर क्यूआर कोड उपलब्ध है. क्यूआर कोड स्कैन करने पर विद्यार्थी का नाम, गांव, रक्त समूह, फोटो, माता-पिता के नाम तथा मोबाइल नंबर जैसी जानकारी सामने आ जाती है. डिजिटल तकनीक आधारित यह पहचान पत्र विद्यार्थियों की सुरक्षा और पहचान के लिए उपयोगी माना जा रहा है. नागपुर जिले में वर्तमान में पीएम श्री योजना के तहत 32 स्कूल संचालित हैं, जिनमें नगर परिषद और जिला परिषद के विद्यालय शामिल हैं. इन स्कूलों में 5,726 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. वहीं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले में 1,512 स्कूल हैं,